***hRegarding uniform wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)-laid**

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की योजना मनरेगा के कार्यक्रम व क्रियान्वयन हेतु देश के सभी राज्यों में ब्लॉक व जिला स्तर पर कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई। सभी राज्यों में इनका कार्य एक समान है, किन्तु वेतन व भत्ता अलग-अलग निर्धारित है एवं संविदा कर्मी होने के कारण इन्हें प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का नवीनीकरण करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मनरेगा, केन्द्र सरकार की योजना है, इसलिए मनरेगा कर्मियों को समान काम-समान वेतन के साथ-साथ नियमितीकरण करने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूं कि इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ।